tonnes of pig iron at concessional rate of duties.

Drought affected vintages in Orissa

1844. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have declared some villages in Orissa as drought affected villages;

(b) if so, the total number of villages in different districts of Orissa which have declared as drought affected; and

(c) the steps taken to provide relief in those villages?

THE MINISTER OF STATE IN-THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Closing of fertiliser units

1845. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of fertilizer units closed down during the last three years;

(b) whether the Fertilizer units functioning at Talcher in Orissa has also been closed down;

(c) if so, the year since when that Fertilizer unit has been closed down; and

(d) the steps taken by Government in the revival of that unit?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) M/s. Hari Fertilizers Ltd., Varanasi, a private sector company was closed down in July 1988 due to economic contraints.

(b) to (d) No, Sir. However, the Talcher Fertilizer plants of Ms. Fertilizer Corporation of India was shut down in May, 198S for taking up annual maintenance jobs. The Plan was thereafter restarted in December 1988 after maintenance and rectification of defects identified during the inspection.

Non-payment of employees' share of Provident Funds contribution by. M/s. Jugantar Ltd. and Amrit Bazar Patrika

1846. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to tbe reply to Starred Question 325 given in the Rajya Sabha on the 19th August, 1988 and state:

(a) whether M/s. Jugantar Ltd. have paid employees share of Provident Funds contribution for the year 1988-89;

(b) whether the Amrit Bazar Patrika have since deposited the employees' share of Provident Fund contributions fully for the 1987-88 and 1988-89;

(c) whether it is a fact that Employer's matching contributions have not been deposited to the Provident Funds of M/s. Jugantar and M/s. Amrit Bazar for several years;

(d) if so, the total arrears of Employer's matching contributions both for Jugantar and Amrit Bazar till date;

(e) total arrears of both the companies in respect of both employer's matching contributions and employees' contributions deducted from the employees' wages till date; and

(f) if defaulted, actions taken and proposed to be taken to recover the arrears?

THE DEPUTY. MINTSTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER. IN THE MINIS TRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) to (f) The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Report of the Bach wat Wage Board

1847.,SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 370 given in the Rajya Sabha on the 4th November, 1988 and state:

(a) whether the Bachwat Wage Board have since submitted its final report;

(b) if so, the salient features of the report; and

(c) what is Government's decision thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER-IN THE MINIS TRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

दिल्ली में राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जा रही राशन की वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार

1848. **श्री रजनी रंजन साहू:** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राशन की दुकानों में उपलब्ध राशन की वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिन के संबंध में गत कुछ माह से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) दुकानदारों द्वारा कालाबाजारी किए जाने पर रोक लगाने हेतु क्या क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा लगातार शिकायतें किए जाने के बावजूद उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध उपभोक्ता वस्तुओं की नियमित आपूर्ति को बनाये रखने के कार्य में कोई सुधार न किए जाने के क्या कारण है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा): (क) भारतीय खाद्य निगम के तकनीकी कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करते हैं कि दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दी जाने वाली विशिष्ट खाद्य वस्तुएं विशिष्टियों के अनुसार हों। निगम के कर्मचारी भी सुपुदर्गी लेने से पूर्व गुणवत्ता की जांच करते हैं। उचित दर की दुकान के मालिकों को अपनी दुकानों पर प्रदर्शित करने के लिए विशिष्ट खाद्य वस्तुओं के सील बंद नमूने सप्लाई किए जाते हैं ताकि खाद्य कार्ड धारी खरीदी जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की सीलबंद नमूनों से तुलना कर सकें। तथापि, यदि उचित दर की दुकानों को कोई ऐसा स्टाक दे दिया जाता है, जो विशिष्टयों के अनुरूप नहीं है तो उचित दर के दुकानधारी सुपुदर्गी की प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर सर्किल अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो स्टॉक विशिष्टयों के अनुरूप नहीं होता है उसे शीघ्र बदल दिया जाता है।

(ख) सामान्य उपायों के अलावा, प्रशासन ने एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है, जो प्रातः 8 बजे से 9 बजे रात तक कार्य करता है। खाद्य कार्ड धारक कदाचार करने वाले उचित दर की दुकान के दुकान धारियों के विरूद्ध टेलीफोन से अथवा लिखित रूप में शिकायत कर सकते हैं। इन शिकायतों की जांच की जाती है और दोषी उचित दर की दुकान के दुकान धारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

(ग) दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम आमतौर पर उचित दर की दुकानों को नियत कार्यक्रम के अनुसार विशिष्ट खाद्य वस्तुओं (गेहूं, चावल तथा चीनी) की सुपुदर्गी करता है। इस संबंध में प्रगति की परिवीक्षा आयुक्त द्वारा पाक्षिक आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन की जाती है। तथापि, इतने बड़े व विस्तुत इस कार्य में प्रचालन संबंधी समस्याओं के कारण कभी-कभी देरी हो ही जाती है।